

## अनुक्रमणिका

क्र. सं.	टॉपिक का नाम
1.	'प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान' के तहत राज्य स्तरीय पुरस्कार
2.	'मुख्यमंत्री विकसित ग्राम-वार्ड अभियान' का शुभारंभ
3.	न्यूज़ इन शॉर्ट्स 1. खाद्य सुरक्षा के प्रशिक्षण में राजस्थान का विश्व रिकॉर्ड 2. भगवान अटलानी (जयपुर) को सिंधी भाषा का साहित्य अकादमी अवॉर्ड 3. जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग एवं AIWC के मध्य MoU 4. "बर्डिंग बाय इयर" (Birding by Ear) पहल 5. उप-मुख्यमंत्री दिया कुमारी को डी.लिट की मानद उपाधि 6. वासुदेव देवनानी को विद्या वाचस्पति की मानद उपाधि 7. "भारत की विश्व विरासत : राजस्थान" प्रदर्शनी : जोधपुर 8. IIT जोधपुर द्वारा विकसित AI-पावर्ड 'इलेक्ट्रॉनिक नोज़' 9. "भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलन" योजना में राजस्थान 10. मुख्यमंत्री ने 207 नवीन बसों को दिखाई हरी झण्डी
4.	भारत बना 'विश्व एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप- 2028' का मेजबान देश
5.	विक्रम दोराईस्वामी
6.	NPCI BHIM सर्विसेज लिमिटेड (NBSL) और एम.एस. धोनी साझेदारी
7.	भारत औद्योगिक विकास योजना (BHAVYA)
8.	लघु जल विद्युत (Small Hydro Power - SHP) विकास योजना
9.	विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट (World Happiness Report) 2026



## राजस्थान परिदृश्य



### 'प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान' के तहत राज्य स्तरीय पुरस्कार



चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, 'प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान' के तहत श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले चिकित्सकों और संस्थानों को राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया।



मुख्य बिन्दु:

- आयोजन स्थल : राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर।

सम्मानित व्यक्तित्व/संस्थान:

क्रम	श्रेणी	सम्मानित व्यक्तित्व/संस्थान
1.	राजकीय चिकित्सा संस्थान	प्रथम - भीनमाल CHC (जालौर) द्वितीय - सुमेरपुर CHC (पाली) तृतीय - मेड़ता CHC (नागौर)

	(अधिकतम उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की पहचान करने व अधिकतम 4 प्रसवपूर्व जाँचों की उपलब्धि हेतु)	
2.	निजी चिकित्सकों की व्यक्तिगत पुरस्कार श्रेणी (प्रसवपूर्व जाँच सेवाओं में उत्कृष्टता हेतु)	प्रथम - डॉ. रंजना गुप्ता। द्वितीय - डॉ. प्रियंका माहेश्वरी। तृतीय - डॉ. निधि बंसल।

## अन्य पुरस्कार :

- अधिकतम गर्भवती लाभार्थियों को PMSA के तहत अधिकतम सेवाएँ सुलभ कराने और लक्ष्य से अधिक PMSA सत्रों का संचालन करने की श्रेणी में 6 जिलों को विशिष्ट अवार्ड दिये गये।
- उच्च प्राथमिकता वाले जिलों के वर्ग में उदयपुर, राजसमंद व बूंदी को और गैर उच्च प्राथमिकता वाले जिलों में जयपुर-1, बीकानेर और कोटा जिलों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार प्रदान किये गये हैं।

## फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स (प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान):

- शुरुआत : 9 जून, 2016 को।
- संबंधित मंत्रालय : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW)
- उद्देश्य : गर्भवती महिलाओं को सार्वभौमिक, मुफ्त और उच्च गुणवत्ता वाली प्रसव-पूर्व देखभाल (ANC) प्रदान करना, ताकि मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम किया जा सके।
- अभियान के तहत हर महीने की 9 तारीख को सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं की प्रसूति विशेषज्ञों या डॉक्टरों द्वारा निःशुल्क जाँच की जाती है।

## 'मुख्यमंत्री विकसित ग्राम-वार्ड अभियान' का शुभारंभ



### चर्चा में क्यों?

- राजस्थान दिवस - 2026 (19 मार्च) के अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा 'मुख्यमंत्री विकसित ग्राम-वार्ड अभियान' का शुभारम्भ किया गया।



### मुख्य बिन्दु:

- **उद्देश्य** : राजस्थान के प्रत्येक ग्राम और शहरी वार्ड के विकास के लिए एक स्थानीय 'मास्टर प्लान' तैयार करना, जो 2047 तक के विकसित राजस्थान के दृष्टिकोण (विकसित राजस्थान@2047) के अनुरूप हो।
- **अवधि** : 19 मार्च से 15 मई, 2026 तक।
- अभियान के अंतर्गत 20 मार्च, 2026 को प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में 'ग्राम सभा' और शहरी क्षेत्रों में 'वार्ड सभा' का आयोजन किया जाएगा।
- इसके तहत अल्पकालिक (2030), मध्यकालिक (2035) और दीर्घकालिक (2047) लक्ष्य निर्धारित कर स्थानीय आवश्यकताओं और संसाधनों के आधार पर विकास योजनाएँ बनाई जाएँगी।
- स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाना, आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करना और आमजन के जीवन स्तर में सुधार लाना इस अभियान की प्राथमिकता है।

### फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स:

#### हालिया चर्चित राजस्थान की प्रमुख ग्राम पंचायतें:

- **बामनवास कांकड़ (कोटपूतली-बहरोड़)** : राजस्थान की पहली पूर्णतः जैविक-प्रमाणित ग्राम पंचायत।
- **सवाईपुरा (पाली)** : विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत 'काउंसिल ऑफ़ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च (CSIR)' द्वारा 'स्मार्ट विलेज मिशन मोड प्रोजेक्ट' का शुभारंभ।
- **पिंडावल (डूंगरपुर)** : पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी 'पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स (PAI)' में राज्य में पहले पायदान पर।
- **खैराबाद (कोटा)** : प्रदेश का पहला स्टील बर्तन बैंक 23 मार्च, 2025 को स्थापित।
- **देसूला (अलवर)** : अगस्त, 2025 में देश की पहली ऐसी ग्राम पंचायत बनी, जहाँ सभी निवासियों को बीमा कवर प्रदान किया गया।

## ✂ न्यूज़ इन शॉर्ट्स ⚡

क्र. सं.	न्यूज़
1.	<p><b>खाद्य सुरक्षा के प्रशिक्षण में राजस्थान का विश्व रिकॉर्ड</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>राजस्थान खाद्य सुरक्षा आयुक्तालय द्वारा 2 दिनों में 48,000 से अधिक खाद्य कारोबारियों को प्रशिक्षण दिया गया। इसे 'वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, लंदन' में दर्ज किया गया।</li><li><b>उद्देश्य :</b> प्रदेश के लोगों को शुद्ध और सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना और व्यापारियों को मानकों के प्रति जागरूक करना।</li></ul>
2.	<p><b>भगवान अटलानी (जयपुर) को सिंधी भाषा का साहित्य अकादमी अवॉर्ड</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>हाल ही में, साहित्य अकादमी द्वारा जयपुर निवासी साहित्यकार भगवान अटलानी को सिन्धी भाषा के लिए वर्ष 2025 के साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया।</li><li><b>कृति का नाम:</b> "वाघू", सिंधी कहानी संग्रह।</li></ul>
3.	<p><b>जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग एवं AIWC के मध्य MoU</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>राजस्थान के जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग और ऑस्ट्रेलिया-इंडिया वॉटर सेंटर (AIWC) के मध्य हाल ही में एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए।</li><li>इस समझौते का मुख्य उद्देश्य जल प्रबंधन, भू-संरक्षण और सुरक्षित पेयजल के क्षेत्र में नवीनतम ऑस्ट्रेलियाई और भारतीय तकनीकों का आदान-प्रदान करना है।</li></ul>
4.	<p><b>"बर्डिंग बाय इयर" (Birding by Ear) पहल</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>अजमेर वन प्रभाग ने हाल ही में प्रकृति को सभी के लिए अधिक सुलभ बनाने हेतु "बर्डिंग बाय इयर" (Birding by Ear) पहल शुरू की।</li><li>"बर्डिंग बाय इयर" (Birding by Ear) पहल के तहत दृष्टिबाधित बच्चों को पक्षियों की आवाज़ सुनकर पहचानना सिखाया जाता है।</li><li>राज्य में अपनी तरह की ये अनूठी पहल समावेशिता, गरिमा और प्रकृति तक समान पहुँच के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।</li></ul>

5.	<p><b>उप-मुख्यमंत्री दिया कुमारी को डी.लिट की मानद उपाधि</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>उप-मुख्यमंत्री दिया कुमारी को जयपुर की आईआईएस यूनिवर्सिटी (IIS Deemed to be University) द्वारा डी.लिट (D.Litt.) की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया।</li><li>यूनिवर्सिटी की ओर से सामाजिक एवं सामुदायिक सेवा क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए उन्हें इस उपाधि से सम्मानित किया गया।</li></ul>
6.	<p><b>वासुदेव देवनानी को विद्या वाचस्पति की मानद उपाधि</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>कुलाधिपति एवं राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने हाल ही में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को 'विद्या वाचस्पति' की मानद उपाधि से विभूषित किया।</li><li>उन्हें यह उपाधि बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षा व समाज के लिए किये गये बेहतरीन नवाचारों हेतु प्रदान की गई है।</li><li>राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष देश के विधानमण्डलों में पहले स्पीकर हैं, जिन्हें शिक्षा व समाज के क्षेत्र में उत्कर्ष नवाचारों के लिए विद्या वाचस्पति की मानद उपाधि से विभूषित किया गया है।</li></ul>
7.	<p><b>"भारत की विश्व विरासत : राजस्थान" प्रदर्शनी : जोधपुर</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>आयोजक</b> : राष्ट्रीय अभिलेखागार, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार।</li><li><b>आयोजन</b> : 14 से 23 मार्च, 2026 तक।</li><li><b>आयोजन स्थल</b> : जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय (JNVU), जोधपुर।</li><li>इस प्रदर्शनी में राजस्थान के प्रमुख सांस्कृतिक अंचलों; मेवाड़, मारवाड़, डूंडाड़ और हाड़ौती की समृद्ध विरासत को दर्शाया गया है।</li><li>राष्ट्रीय अभिलेखागार, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक संलग्न कार्यालय है। इसकी स्थापना 11 मार्च, 1891 को कोलकाता (तत्कालीन कलकत्ता) में 'इम्पीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट' के रूप में हुई थी।</li></ul>

8.	<p><b>IIT जोधपुर द्वारा विकसित AI-पावर्ड 'इलेक्ट्रॉनिक नोज़'</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) जोधपुर के शोधकर्ताओं ने एक AI-पावर्ड 'इलेक्ट्रॉनिक नोज़' (Electronic Nose) विकसित की है, जो इंसान की सांस के ज़रिए बीमारियों का पता लगाने में सक्षम है।</li><li>■ यह टेक्नोलॉजी सांस में मौजूद वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स (VOCs) का विश्लेषण करके बीमारियों के शुरुआती लक्षणों की पहचान करती है।</li></ul>
9.	<p><b>"भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलन" योजना में राजस्थान</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ केंद्र सरकार द्वारा देश भर में सामुदायिक आधारित प्रसारण को बढ़ावा देने के लिए 'भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलन' नामक केन्द्रीय क्षेत्र योजना का संचालन किया जा रहा है।</li><li>■ अप्रैल, 2021 से फरवरी, 2026 की अवधि के दौरान देश भर में कुल 149 सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की गई है, जिनमें राजस्थान के 8 स्टेशन शामिल हैं।</li></ul>
10.	<p><b>मुख्यमंत्री ने 207 नवीन बसों को दिखाई हरी झण्डी</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ मुख्यमंत्री द्वारा राजस्थान दिवस के अवसर पर जयपुर से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की 207 नवीन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।</li><li>■ इन बसों में RSRTC की ओर से सर्विसलाइन पर ली गई 100 ब्लूलाइन एक्सप्रेस बसें, 79 स्टारलाइन बसें तथा 28 वातानुकूलित बसें शामिल हैं।</li></ul>



## राष्ट्रीय परिदृश्य



### भारत बना 'विश्व एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप- 2028' का मेजबान देश

#### चर्चा में क्यों?

- पोलैंड के टोरून में आयोजित विश्व एथलेटिक्स परिषद की बैठक के दौरान भारत को 'विश्व एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप- 2028' की मेजबानी दी गई।

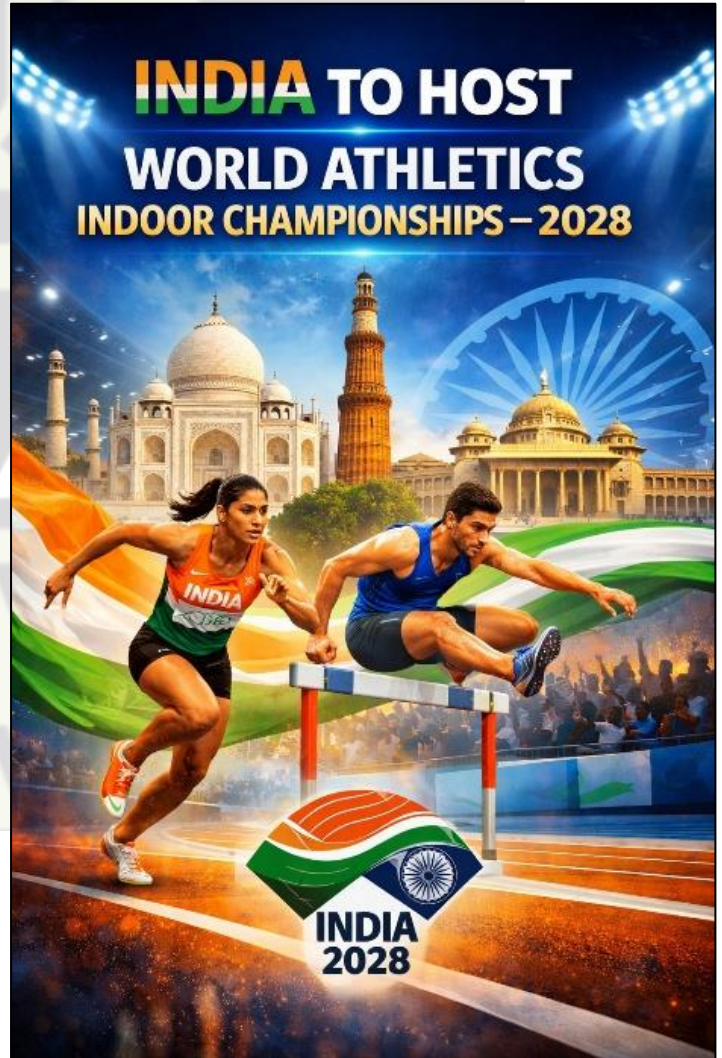
#### मुख्य बिन्दु:

- यह पहला मौका है जब भारत किसी ग्लोबल ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। साथ ही, जापान (1999), कतर (2010) और चीन (2025) के बाद भारत यह उपलब्धि हासिल करने वाला चौथा एशियाई देश है।

- प्रतियोगिता का आयोजन : भुवनेश्वर, ओडिशा।

- अवधि : 3 से 5 मार्च, 2028 तक।

- चैंपियनशिप की सभी स्पर्धाएँ भुवनेश्वर के कलिंगा इंडोर एथलेटिक्स स्टेडियम में होंगी।



# Daily Current Affairs

Date : 20 March, 2026



**फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स:**

**हालिया समय में भारत में आयोजित अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताएँ:**

आयोजन	खेल	स्थान
ICC महिला क्रिकेट विश्व कप - 2025	क्रिकेट	विभिन्न शहर
वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल	मुक्केबाजी	नई दिल्ली
सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल	बैडमिंटन	लखनऊ
पुरुष FIH हॉकी जूनियर विश्व कप	हॉकी	चेन्नई/मदुरै
WSF स्क्वैश वर्ल्ड कप	स्क्वैश	चेन्नई
ICC पुरुष T20 विश्व कप - 2026	क्रिकेट	विभिन्न शहर
एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप	भारोत्तोलन	अहमदाबाद
BWF विश्व चैंपियनशिप 2026	बैडमिंटन	नई दिल्ली

--9--

## विक्रम दोराईस्वामी



### मुख्य बिन्दु:

- **स्थिति:** वरिष्ठ राजनयिक और 1992 बैच के भारतीय विदेश सेवा (IFS) अधिकारी, जिन्हें 19 मार्च, 2026 को भारत का अगला राजदूत चीन में नियुक्त किया गया। वर्तमान में भारत के यूनाइटेड किंगडम में उच्चायुक्त हैं।
- **वर्तमान स्थिति (मार्च, 2026 तक):** बीजिंग में प्रदीप कुमार रावत का स्थान लेने के लिए नियुक्त। यह कदम 2020-2024 लद्दाख स्टैंडऑफ के बाद भारत-चीन संबंधों को स्थिर करने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।



### पूर्व प्रमुख भूमिकाएँ:

- **यूके में उच्चायुक्त (2022-2026):** जुलाई, 2025 में भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के दौरान प्रमुख भूमिका निभाई।
- **बांग्लादेश में उच्चायुक्त (2020-2022):** महत्वपूर्ण "Neighbourhood First" नीति पहल और कनेक्टिविटी परियोजनाओं का संचालन।
- **दक्षिण कोरिया (2015-2018) और उज़्बेकिस्तान (2014-2015) में राजदूत।**

## आर्थिक घटनाक्रम

### NPCI BHIM सर्विसेज लिमिटेड (NBSL) और एम.एस. धोनी साझेदारी

#### चर्चा में क्यों?

- मार्च, 2026 में, NPCI BHIM सर्विसेज लिमिटेड (NBSL) ने पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी को अपने डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म BHIM (Bharat Interface for Money) का ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया है।

#### मुख्य बिन्दु:

- नया ब्रांड विजन:** इस साझेदारी के साथ BHIM को "भारत का अपना पेमेंट्स ऐप" (Bharat Ka Apna Payments App) के रूप में री-पोजिशन किया गया है।
- रणनीतिक उद्देश्य:** इसका मुख्य लक्ष्य डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में भरोसा (Trust) और सादगी (Simplicity) को बढ़ावा देना है, विशेष रूप से टियर-2, टियर-3 शहरों और ग्रामीण भारत में।
- संगठनात्मक संरचना:** BHIM ऐप का प्रबंधन अब NBSL द्वारा किया जाता है, जो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।
- प्रतिस्पर्धा और समावेशन:** यह कदम निजी फिनटेक दिग्गजों (जैसे PhonePe और Google Pay) के बीच BHIM की बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने और वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) को सुदृढ़ करने की रणनीति का हिस्सा है।



## परीक्षा के लिए महत्त्वपूर्ण तथ्य:

- **BHIM ऐप:** इसे 30 दिसंबर, 2016 को लॉन्च किया गया था। यह UPI (Unified Payments Interface) पर आधारित है।
- **NBSL का गठन:** NPCI ने BHIM के संचालन को अधिक केंद्रित और व्यावसायिक बनाने के लिए इस अलग इकाई (NBSL) का गठन किया है।
- **आधार (Technology):** यह UPI (Unified Payments Interface) तकनीक पर आधारित है, जो IMPS (Immediate Payment Service) का उन्नत संस्करण है।

## मुख्य तकनीकी विशेषताएँ:

- **त्रि-स्तरीय सुरक्षा (Three-level Authentication):** इसमें डिवाइस बाइंडिंग (Device Binding), ऐप पिन (App PIN) और यूपीआई पिन (UPI PIN) के माध्यम से सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है।
- **बिना इंटरनेट (USSD आधारित):** BHIM की एक बड़ी विशेषता यह है कि इसे बिना इंटरनेट वाले फीचर फोन पर \*99# डायल करके भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
- **बहुभाषी समर्थन (Multilingual Support):** यह वर्तमान में 20 भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं को सपोर्ट करता है, जो इसे ग्रामीण भारत के लिए सुलभ बनाता है।
- **भुगतान के तरीकें:** इसमें वर्चुअल पेमेंट एड्रेस (VPA), मोबाइल नंबर, QR कोड और आधार नंबर (Aadhaar-linked accounts) के जरिए पैसे भेजे जा सकते हैं।
- **नियामक (Regulator):** UPI और BHIM का समग्र विनियमन भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा किया जाता है।

## योजनाएँ एवं नीतियाँ

### भारत औद्योगिक विकास योजना (BHAVYA)

#### चर्चा में क्यों?

- औद्योगिक विकास को तेज़ी प्रदान करने के दृष्टिकोण से हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत औद्योगिक विकास योजना (BHAVYA) को स्वीकृति प्रदान की।

Ai- Generated image



# BHAVYA

Bharat Audyogik Vikas Yojna

-  Cabinet approves **Bharat Audyogik Vikas Yojna (BHAVYA)** to develop **100 plug-and-play industrial parks** with an allocation of **₹ 33,660 crore**
-  Scheme aims to develop **world-class industrial infrastructure**, unlocking manufacturing potential and driving India's growth story
-  Industrial parks from **100 to 1000 acres** to be developed with support of up to **₹ 1 crore per acre**
-  BHAVYA to be implemented with **states and private sector**, under the **National Industrial Corridor Development Programme** framework



CABINET DECISION  
18-03-2025

## मुख्य बिन्दु:

- **लक्ष्य** : इस योजना के तहत पूरे देश में 100 'प्लग-एंड-प्ले' औद्योगिक पार्क विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है।
- **प्लग-एंड-प्ले मॉडल** : इसका अर्थ है कि उद्योगों के लिए पहले से स्वीकृत भूमि, बिजली, पानी, सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाएँ तैयार मिलेंगी, जिससे कंपनियाँ बिना देरी के अपना उत्पादन शुरू कर सकेंगी।
- **उद्देश्य** : विश्व-स्तरीय औद्योगिक बुनियादी ढांचा तैयार करना, मैनुफैक्चरिंग की संभावनाओं को खोलना।
- **क्रियान्वयन एजेंसी** : नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NICDC), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय।
- इस योजना के तहत 100 से लेकर 1000 एकड़ तक के औद्योगिक पार्कों को विकास के लिए चुना जाएगा। साथ ही, मुख्य बुनियादी ढांचा, मूल्य-वर्धित बुनियादी ढांचा और सामाजिक बुनियादी ढांचा के लिए प्रति एकड़ ₹1 करोड़ तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी:
- **योजना के तहत लाभार्थी** :
- **प्राथमिक लाभार्थी** : विनिर्माण इकाइयाँ, MSME, स्टार्टअप और ऐसे वैश्विक निवेशक जिन्हें उपयोग के लिए तैयार औद्योगिक बुनियादी ढांचे की आवश्यकता है।
- **द्वितीयक लाभार्थी** : श्रमिक, लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदाता, सेवा क्षेत्र के उद्यम और स्थानीय समुदाय।


## लघु जल विद्युत (Small Hydro Power - SHP) विकास योजना



चर्चा में क्यों?

- केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में लघु जल विद्युत (Small Hydro Power - SHP) विकास योजना को मंजूरी दी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के दूर-दराज और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ ऊर्जा पहुँचाना है।


AI-Generated image



### SMALL HYDRO POWER (SHP) DEVELOPMENT SCHEME

- Cabinet approves **Small Hydro Power (SHP) Development Scheme** for FY 2026-27 to FY 2030-31 with an outlay of **₹ 2584.60 crore** for approx. **1500 MW** capacity
- Scheme to support **small hydro projects (1-25 MW)** across states, especially benefiting hilly and **North Eastern states**
- Central financial assistance up to **₹ 3.6 crore per MW** or 30% of project cost for **North Eastern states and border districts**, with a cap of **₹ 30 crore** per project
- Central financial assistance up to **₹ 2.4 crore per MW** or 20% of project cost for **other states**, with a cap of **₹ 20 crore** per project

CABINET DECISION- 18-03-2026



-:15:-

## मुख्य बिन्दु:

- **अवधि** : वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक।
- यह योजना अलग-अलग राज्यों में छोटे हाइड्रो प्रोजेक्ट (1-25 MW क्षमता वाले) लगाने में मदद करेगी जिससे खास तौर पर पहाड़ी और उत्तर-पूर्वी राज्यों को फ़ायदा होगा, जहाँ ऐसे प्रोजेक्ट्स की बहुत ज़्यादा संभावना है।
- **लक्ष्य** : अगले 5 वर्षों में लगभग 1,500 मेगावाट (MW) क्षमता के छोटे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स स्थापित करना।
- **क्रियान्वयन** : नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE)
- **नोट** : भारत में 1 से 25 मेगावाट तक की क्षमता वाले प्रोजेक्ट्स को 'लघु जल विद्युत' (SHP) प्रोजेक्ट्स की श्रेणी में रखा जाता है।
- इस योजना के तहत मशीनों और उपकरणों का 100 प्रतिशत निर्माण भारत में होना अनिवार्य है।

## वित्तीय सहायता (CFA)

क्षेत्र	वित्तीय सहायता	अधिकतम सीमा
पूर्वोत्तर राज्य और सीमावर्ती जिले	₹3.6 करोड़ प्रति मेगावाट	₹30 करोड़
अन्य सभी राज्य	₹2.4 करोड़ प्रति मेगावाट	₹20 करोड़



## अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य



### विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट (World Happiness Report) 2026



#### मुख्य बिन्दु:

#### 1. रिपोर्ट का अवलोकन (Report Overview)

- प्रकाशन तिथि: 19 मार्च, 2026 (प्रतिवर्ष 20 मार्च को 'अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस' के अवसर पर जारी की जाती है)।
- संस्करण: 14वाँ संस्करण (प्रथम प्रकाशन 2012 में)।
- प्रकाशक संस्थाएँ: ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के 'वेलबीइंग रिसर्च सेंटर' द्वारा गैलप (Gallup) और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क (UNSDSN) के सहयोग से निर्मित।
- 2026 का विषय (Theme): "प्रसन्नता और सोशल मीडिया" (Happiness and social media)।

#### 2. भारत का प्रदर्शन (प्रारंभिक/मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण)

- रैंक: 147 देशों में 116वां स्थान।
- प्रवृत्ति (Trend): 2025 में 118वें और 2024 में 126वें स्थान की तुलना में आंशिक सुधार।
- जीवन मूल्यांकन स्कोर: 10 में से 4.536।
- क्षेत्रीय तुलना: भारत नेपाल (99वें) और पाकिस्तान (104वें) से पीछे है, लेकिन बांग्लादेश (127वें) और श्रीलंका (134वें) से आगे है।
- मजबूती बनाम कमजोरी:
  - मजबूती: भ्रष्टाचार का बोध (64वाँ), उदारता (78वाँ) और स्वतंत्रता (61वाँ)।
  - कमजोरी: सामाजिक सहयोग (123वां) और प्रति व्यक्ति जीडीपी (89वां) समग्र स्कोर में बड़ी बाधाएँ हैं।

### 3. वैश्विक रैंकिंग और रुझान

- सबसे खुशहाल देश: फिनलैंड (लगातार 9वें वर्ष शीर्ष पर)।
- शीर्ष 5 देश: फिनलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क, कोस्टा रिका (किसी लातिन अमेरिकी देश के लिए अब तक की सर्वोच्च रैंकिंग) और स्वीडन।
- सबसे कम खुशहाल देश: अफगानिस्तान (147वाँ), उसके बाद सिएरा लियोन (146वाँ) और मलावी (145वाँ)।
- अंग्रेजी भाषी राष्ट्र: लगातार दूसरे वर्ष शीर्ष 10 में से कोई भी शामिल नहीं (अमेरिका: 23वाँ, कनाडा: 25वाँ, यूके: 29वाँ)।

### 4. कार्यप्रणाली: 6 प्रमुख पैरामीटर

- रैंकिंग 'कैट्रिल लैडर' (स्व-रिपोर्ट की गई जीवन संतुष्टि) पर आधारित है और इसे छह चरों (Variables) द्वारा स्पष्ट किया गया है:
  1. प्रति व्यक्ति जीडीपी (क्रय शक्ति समानता - PPP)
  2. सामाजिक सहयोग (मुसीबत में साथ देने वाला कोई हो)
  3. स्वस्थ जीवन प्रत्याशा
  4. जीवन विकल्प चुनने की स्वतंत्रता
  5. उदारता (दान करने की प्रवृत्ति)
  6. भ्रष्टाचार का बोध (सरकार और व्यवसाय में)

### 5. विशेष फोकस 2026: सोशल मीडिया और युवा

- युवा कल्याण संकट: पश्चिमी देशों में 25 वर्ष से कम आयु के लोगों की प्रसन्नता में भारी गिरावट देखी गई।
- स्क्रीन टाइम का संबंध: अधिक उपयोग (प्रतिदिन 5+ घंटे) जीवन संतुष्टि में कमी से जुड़ा है, विशेष रूप से किशोरियों में।
- इष्टतम उपयोग (Optimal Use): सोशल मीडिया का मध्यम उपयोग (प्रतिदिन <1 घंटा) बिल्कुल उपयोग न करने की तुलना में बेहतर मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा है।